प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

09.05.2026 / प्रादेशिक समाचार / 11:00बजे

टैगोर–जयंती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि टैगोर की रचनाएं मानवता, भाईचारे और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। 'गीतांजलि' ने मानवता और आध्यात्म को नई राह दिखाई, जबकि 'जन गण मन' ने देश की एकता और सम्मान को स्वर दिया।

पंचायत चुनाव

प्रदेश की 3 हजार 7 सौ 54 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25 हजार 6 सौ 71 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरूआती दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42 हजार पांच सौ 62 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी। ––डिस्पैच––

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5 हजार 9 सौ 89, जबकि लाहौल स्पीति जिला में सबसे कम 2 सौ 9 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4 हजार एक सौ 80, शिमला में 2 हजार 6 सौ 75, चम्बा में दो हजार 5 सौ 81, ऊना में एक हजार 9 सौ 41, सिरमौर में एक हजार 7 सौ 97, हमीरपुर में एक हजार 5 सौ 48, सोलन में एक हजार 5 सौ 43, कुल्लू में एक हजार 5 सौ 4, बिलासपुर में एक हजार 2 सौ 81, किन्नौर में 4 सौ 23, नामांकन पत्र दर्ज किए गए। प्रादेशिक समचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।

इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31 हजार एक सौ 82 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे।

संशोधन

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायतीराज संस्थाओं के लिए सात दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2 तिहाई कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे।

लोक अदालत

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63 हजार मामले प्राप्त हुए हैं।

फसल सर्वेक्षण– डिस्पैच

डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है जिससे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर, कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केन्द्र की इस योजना के तहत, प्रदेश के 93 हज़ार 870 राजस्व गाँवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आँकड़े, सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक व्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट.....

वर्ष 2023–24 में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक डेटा एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है जिस से किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर, कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सकेगी । देश में प्रत्येक खेत की जियो–टैगिंग के साथ, बोई गई फसलों की तस्वीरें ली जाती हैं जिससे हर फसल चक्र में फसल उत्पादन अनुमान, फसल बीमा का समय पर वितरण और एग्री स्टैक योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं का सही लाभ किसान तक पहुंचाना, इस सर्वेक्षण का लक्ष्य है । योजना के तहत, हिमाचल प्रदेश के 93 हज़ार 870 राजस्व गाँवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आँकड़े, सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं प्रादेशिक समाचार के लिए ऊना से मैं राजेश कुमार शर्मा।

बर्ड काउंट

हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षिओं की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरूआत वर्ष 2022 से की गई थी। विशेषज्ञों के

अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वालो क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10 प्रतिशत पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई–बर्ड मोबाइल एप्प के माध्यम से अपलोड कर सकेंगे।

इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे नमस्कार।